कश्मीर से सेना को वापस बुलाने के फैसले के बाद घुसपैठ में वृद्धि

*42. **श्री अमरेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर में संवेदनशील क्षेत्रों से सेना को वापस बुलाने के फैसले के कारण सीमापार से घुसपैठ दोगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण कश्मीर के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं; और

(घ) कश्मीर में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ बातचीत का औचित्य क्या है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य से सेना को वापस नहीं बुलाया गया है। सीमा पार से अधिक से अधिक आतंकवादियों को यहां भेज कर हिंसा का स्तर बढ़ाने के आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों और उनकी निरंतर बदलती चालों का मुकाबला करने के लिए वास्तविक आकलन के आधार पर रणनीतियों, युक्तियों और नीतिशील तैनाती की राज्य में एकीकृत मुख्यालय और विभिन्न स्तरों पर ऑपरेशन ग्रुपों में निरंतर समीक्षा की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और उसकी मानीटरिंग की जाती है। गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान अनुमानित 92 आतंकवादियों की घुसपैठ की तुलना में 30 जून, 2006 तक सीमा पार से अनुमानत: 299 आतंकवादियों ने घुसपैठ की।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार आतंकवाद से निपटने और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना और जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से निपटने के लिए प्रतिकारी उपाय करना, आर्थिक विकास तेज करना, जम्मू और कश्मीर के सभी ग्रुपों और विशेष रूप से उन ग्रुपों, जो हिंसा का मार्ग त्याग देते हैं और वार्ता करने तथा सभी स्तरों पर चुनावों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया मजबूत करते हैं, के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। गत दो वर्षों की तुलना में 15 जुलाई, 2006 तक राज्य में आतंकवादी हिंसा के स्तर में निम्नानुसार कमी आई है।

	2006 (15 जुलाई तक)	2005 (15 जुलाई तक)	2004 (15 जुलाई तक)
आतंकवादी घटनाओं की संख्या	910	1085	1452

इन गतिविधियों से विचलित हो कर, आतंकवादी गुटों ने हाल के महीनों में हताशा में हथगोले फैंक कर, पर्यटकों सहित आसान लक्ष्यों पर हमले करके और हिंसा को साम्प्रदायिक रंग दे कर हिंसा के प्रतीकात्मक कृत्य बढ़ाने का सहारा लिया।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार, उन सभी ग्रुपों, जो हिंसा को त्याग देते हैं, के साथ वार्ता करके और अन्य माध्यमों से जम्मू और कश्मीर से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ वार्ता की जा रही है।

विवरण

(प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय गृह मंत्री द्वारा यथासंशोधित)

(क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाल में राज्य से सेना को वापस नहीं बुलाया गया है। पहले कुछ सेना वापस की गई थी, लेकिन सरकार ने उसके स्थान पर कुछ अधिक बटालियनों की तैनाती करके उस कमी को पूरा कर लिया था। सीमा पार से अधिक से अधिक आतंकवादियों को यहां भेज कर हिंसा का स्तर बढ़ाने के आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों और उनकी निरंतर बदलती चालों का मुकाबला करने के लिए वास्तविक आकलन के आधार पर रणनीतियों, युक्तियों और गतिशील तैनाती की राज्य में एकीकृत मुख्यालय और विभिन्न स्तरों पर आपरेशन ग्रुपों में निरंतर समीक्षा की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और उसकी मानीटरिंग की जाती है। गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान अनुमानित 92 आतंकवादियों की घुसपैठ की तुलना में 30 जून, 2006 तक सीमा पार से अनुमानत: 299 आतंकवादियों ने घुसपैठ की।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार आतंकवाद से निपटने और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना और जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से निपटने के लिए प्रतिकारी उपाय करना, आर्थिक विकास तेज करना, जम्मू और कश्मीर के सभी ग्रुपों और विशेष रूप से उन ग्रुपों, जो हिंसा का मार्ग त्याग देते हैं और

वार्ता करने तथा सभी स्तरों पर चुनावों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया मजबूत करने तथा जम्मू और कश्मीर के अंदर राजनीतिक बहस को प्रोत्साहित करने की इच्छा प्रकट करते हैं, के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। गत दो वर्षों की तुलना में 15 जुलाई, 2006 तक राज्य में आतंकवादी हिंसा के स्तर में निम्नानुसार कमी आई है:—

	2006 (15 जुलाई तक)	2005 (15 जुलाई तक)	2004 (15 जुलाई तक)
आतंकवादी घटनाओं की संख्या	910	1085	1452

इन गतिविधियों से विचलित हो कर, आतंकवादी गुटों ने हाल के महीनों में हताशा में हथगोले फेंक कर, पर्यटकों सहित आसान लक्ष्यों पर हमले करके और हिंसा को साम्प्रदायिक रंग दे कर हिंसा के प्रतीकात्मक कृत्य बढ़ाने का सहारा लिया।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार, उन सभी ग्रुपों, जो हिंसा त्याग देते हैं, के साथ वार्ता करके जम्मू और कश्मीर से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ वार्ता की जा रही है।

Increase in intrusion after withdrawal of troops from Kashmir

†*42. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to the decision to withdraw troops from sensitive areas in Kashmir, infiltrations from across the border have doubled;

(b) if so, the details in this ragard;

(c) whether due to the lax policies of Government, situation in Kashmir is going out of hand; and

(d) the justification for holding talks with the leaders of Hurriyat Conference in Kashmir?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) and (b) As reported by the State Government of Jammu and Kashmir, there has been no withdrawal of troops from the State. To counter the nefarious designs and ever changing tactics of terrorist outfits for escalating the level of violence by pushing in more and more terrorists from across the border, the strategies, tactics and dynamic deployment as per ground assessment are constantly reviewed, refined and monitored in the Unified Headquarters in the State and in Operation Groups at various levels. Till June 30, 2006, an estimated number of 299 terrorists infiltrated from across the border as compared to estimated 92 terrorists during the corresponding period last year.

(c) No, Sir. The State Government of J&K and the Union Government are pursuing a multi pronged strategy to deal with terrorism and bring in peace and normalcy in the State which, *inter-alia*, include strengthening border management and pro active tackling against terrorists within J&K, accelerating the economic development, being open to initiate a dialogue process with all groups in J&K and especially, those who eschew the path of violence and express a desire for such talks, and deepening of political process through elections at all levels and encouraging political debate within J&K. Till July 15, 2006, the situation in the State has witnessed lower levels of terrorist violence over the last two years as follows:

	2006 (upto July 15)	2005 (upto July 15)	2004 (upto July 15)
No. of terrorist incidents	910	1085	1452

Unsettled by these develpoments terrorist outfits have in desperation resorted to escalate demonstrative acts of violence through hurling of hand grenades, attacks on soft targets including tourists and communalizing violence in recent months.

(d) The Govenment of J&K and the Govenment of India are committed to the resolution of all problems related to Jammu and Kashmir through dialogue with all those who abjure violence and other means. Talks with the leaders of Hurriyat Conference are being held in this context.

Statement

(As corrected by the Hon'ble Minister while answering the question)

(a) and (b) As reported by the State Govenment of Jammu and Kashmir, there has been no withdrawal of troops from the State in recent times. Previously, some withdrawal was done but, then, Government had replaced the troops with higher number of the battalion and that way Government had made good the loss. To counter the neferious designs and ever changing tactics of terrorist outfits for escalating the level of violence by pushing in more and more terrorists from across the border, the strategies, tactics and dynamic deployment as per ground assessment are constantly reviewed, refined and monitored in the Unified Headquarters in the State and in Operation Groups at various levels. Till June 30, 2006, an estimated number of 299 terrorists infiltrated from across the border as compared to estimated 92 terrorists during the corresponding period last year.

(c) No, Sir, The State Government of J&K and the Union Government are pursuing a multi pronged strategy to deal with terrorism and bring in peace and normalcy in the State which, *inter-alia*, include strengthening border management and pro active tackling against terrorists within J&K, accelerating the economic development, being open to initiate a dialogue process with all groups in J&K and especially, those who eschew the path of violence and express a desire for such talks, and deepening of political process through elections at all levels and encouraging political debate within J&K. Till July 15, 2006, the situation in the State has witnessed lower levels of terrorist violence over the last two years as follows:

	2006 (upto July 15)	2005 (upto July 15)	2004 (upto July 15)
No. of terrorist incidents	910	1085	1452

Unsettled by these developments, terrorist outfits have in desperation resorted to escalate demonstrative acts of violence through hurling of hand grenades, attacks on soft targets including tourists and communalizing violence in recent months.

(d) The Government of J&K and the Government of India are committed to the resolution of all problems related to Jammu and Kashmir through

dialogue with all those who adjure violence and other means. Talks with the leaders of Hurriyat Conference are being held in this context.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I would like to correct the reply to question No. 42 (a) a little. The first sentence says that "As reported by the State Government of Jammu and Kashmir, there has been no withdrawal of troops from the State". I would like to add "in recent times" to it. Previously, some withdrawal was done but, then, we had replaced the troops with higher number of the battalion and that way we had made good the loss. So, this is the correction I wanted to put on record.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति: आपका धन्यवाद बड़ा खतरनाक होता है।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली और अपना बयान बदल दिया। जब हमें पढ़ा कि राज्य सरकार की सूचना के मुताबिक सेना की कोई टुकड़ी वापस नहीं बुलाई गई, तो हमारा सिर फटने लगा, क्योंकि हम जानते थे कि यह खबर छप रही थी कि सेना वापस बुलाई जा रही है और राज्य सरकार खबर देने वाली कौन होती है? गृह विभाग में जम्मू-कश्मीर का विभाग अलग से है और उस विभाग में गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सब शामिल हैं, बिजली विभाग भी है। जैसा आप स्वीकार कर रहे हैं कि इधर घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है और पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है, उनके हमले भी ज्यादा हुए हैं और हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इसकी जांच की कि ऐसा क्यों हो रहा है? सरहद पर जो एक लंबा-सा तार बिछा था, उसमें बिजली का करेंट भी लगाया जाता था, क्या आपको जानकारी है, अगर जानकारी न हो, तो बिजली मंत्री जी से पूछ लीजिए कि आम तौर से उसमें बिजली की लाइन ही नहीं रहती है और बिजली की लाइन के न रहने से आतंकवादियों को मालूम हो जाता है तथा वे तार तोड़ दिया करते हैं और घुस आते हैं। क्या इसकी जानकारी आपको है? आप जो जनरेटर वहां पर रखते हैं, वहां बिजली की व्यवस्था करने के लिए बल्ब, फ्लैश लाइट वगैरह जो हैं, वे सारे के सारे हमेशा खराब रहते हैं। आपका सुरक्षा तंत्र कैसा है, इसकी तो पोल खुल गई है। यह तो अखबार छाप रहे हैं कि वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस पर हजारों-करोड़ों रुपया खर्च किया गया, विदेशी कंपनियों को ठेका देकर ये तार लगवाए गए हैं और आज यह स्थिति आ गई है कि जनरेटर खराब हैं, इसके कारण घुसपैठिए आएंगे नहीं और आतंकवाद बढ़ेगा नहीं, तो और क्या होगा?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सभापति जी, हमारी जो सीमा है, उसका कुछ हिस्सा पैरा-मिलट्री फोर्सेज के पास है और कुछ हिस्सा आर्मी के पास है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है,

वहां पर पुलिस तैनात की गई है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर आर्मी तैनात की गई है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाड़ हमने वहां पर लगाई है, उसमें कुछ खराबियां पैदा हुई हैं, लेकिन वे खराबियां किस वजह से पैदा हुई है, यह भी देखना पड़ेगा। जो भूकंप परसों आया, उसके बाद वहां बड़े पैमाने पर जो बर्फ वर्षा हुई, उसकी वजह से कुछ जगहों पर जो बाड़ हमने लगाई थी, उसमें कुछ खराबियां जरूर आई हैं। वहां इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हमने जनरेटर्स रखे हैं औ वे जनरेटर्स काम करते हैं। एकाध जनरेटर अगर कहीं बिगड़ गया हो और हम सिर्फ उसकी चर्चा करें, तो वह ठीक नहीं रहेगा। अगर बड़ा जनरेटर वहां पर लगाया गया है और कोई एकाध पुर्जा न होने की वजह से मुश्किल हो गई है, तो पूरी की पूरी लाइन पर लाइट नहीं है या विद्युत नहीं मिल रही है, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है।

एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब-जब हम ऐसी चीजों का मुकाबला करने के लिए कोई कदम उठाते हैं, जब जो खलल पैदा करने वाले लोग होते हैं, आतंकवाद पैदा करने वाले लोग होते हैं, वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, उसके ऊपर कैसे मात करें, उसके बारे में शुरू से ही विचार करते हैं। जिस दिन से यह बाड़ वहां लगाने को काम शुरू हुआ है, उस दिन से, आपने भी पढ़ा होगा और दूसरे बहुत से लोगों ने भी लिखा है कि बाड़ लगाने पर उसको कैसे क्रॉस किया जाए, इस संबंध में टेक्नोलॉजी लेकर या तार को कैसे काटकर या सेंध कैसे लगाकर या रबड़ के कपड़े पहनकर या लकड़ी के हथियार लेकर कैसे उसको क्रास करेंगे, यह करने का काम चलता है। यह जो काम है, यह तो होता ही रहता है ओर उसके ऊपर हमें मात करना है। लेकिन सदन की मालूमात के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो आप कह रहे हैं कि वहां कि संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, यह सही नहीं है। 2004 में वहां पर जो इंसीडेंट्स हुए हैं, वह 1,452 हैं और 2005 में जो इंसीडेंट्स हुए हैं, वह 1,085 थे और उसी पीरियड के अंदर, एक ही पीरियड में, 2006 में जो इंसीडेंट्स हुए हैं, वह 910 हैं। ये कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मंत्री जी ने थोड़ी सी चालाकी दिखा दी। इन्होंने कितनी संख्या वारदात की हुई है, यह बताया है। हमने कहा था, घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसको इनके गृह सचिव ने स्वीकार किया है और प्रणव मुखर्जी साहब की पलटन के जरनैल ने स्वीकार किया है कि वह तादात बढ़ी है। संख्या जब हमने कहा था तो घटनाओं की नहीं, घुसपैठियों की तादात कहा था। हमने अखबार में पढ़ा है कि इन दोनों लोगों ने स्वीकार किया है कि इस बार तादात बढ़ गयी है। खैर, इस संबंध में वे बाद में सफाई देंगे। जिस बाड़ की बात यह कर रहे हैं, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इस समय उसके रख-रखाव पर कितना खर्चा हो रहा है और किन लोगों को उसका ठेका दिया गया है? ठेके के संबंध में क्या ऐसा भी है कि पाकिस्तान की खुफिया ऐजेंसी का या आतंकवादियों का कोई आदमी भी ठेकेदार बन गया है, जैसा कि सुनने को आ रहा है। पता नहीं आजकल कितनी खुफिया ऐजेंसीज़ हमारे देश में काम कर रही हैं। हमारे नेता विरोधी दल ने

तो कह दिया कि प्रधान मंत्री के कार्यालय में भी एक खुफिया आदमी है। इसलिए इस समय हम लोग बड़े चिंतित हैं, खुफिया विभाग से। तो क्या रख-रखाव की ठेकेदारी में खुफिया तंत्र भी काम कर रही है और कितना खर्च इस संबंध में हो रहा है?

श्री शिवराज वी. पाटिल: महोदय, सीमा की सुरक्षा का काम प्राईवेट ठेकेदार की मदद से नहीं हो रहा।

श्री जनेश्वर मिश्र: विदेशी कम्पनी तक को दिया है, बिजली बिछाने का।

श्री शाहिद सिद्दकी: इज़राइल की कम्पनी को दिया है।

†[ ]**شری شاہد صدیقی :** اسرائیل کی کمپنی کو دیا ہے۔[ ]

श्री शिवराज वी. पाटिल: आप जो कह रहे हैं, वह मैंटेनेंस का काम दिया है। यह जो काम वहां का हुआ है, बाड़ लगवाने का, वह हमारी आर्मी के लोगों ने किया है। यह बड़ी अजीब बात है कि हम सदन में उठकर सरकार की ओर से बोल रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा करने के बजाय किसी एक न्यूजपेपर में आया, उसके ऊपर भरोसा करके अगर कोई प्रश्न पूछे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और एक सीनियर मैंबर से हम यह एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि संख्या में कमी आ गयी है, इनफिलट्रेशन जो हुआ है, वह बढ़ा है मगर इंसीडेंट्स जो हुए हैं, वह कम हुए हैं। मैं आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिन लोगों को पकड़ा है, उसकी संख्या बढ़ी है, जिनको मारा है, उनकी संख्या बढ़ी है तथा जो इंसीडेंट्स हुए हैं वह अच्छी बात है। अब कोई बाहर कुछ लिखे, आधे मालूमात पर, लिमिटेड इनफॉर्मेशन के आधार पर, उस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो सदन में कहा जाए, उस पर भरोसा किया जाए।

श्री जनेश्वर मिश्र: कितना खर्चा उसके रखरखाव पर हो रहा है?

श्री शिवराज वी. पाटिल: वह खर्चा मैं आको बाद में लिखकर बता दूंगा।

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Chairman, Sir I am happy that the hon. Minister of Home has corrected the reply by adding, 'in recent times'. But, I am still aboslutely amazed at the first sentence of this reply where he says,".... as reported by the state Government of Jammu and Kashmir, there has been no withdrawal of troops from the state," Now, Sir, all of us; the entire House is aware that the defence of our borders is the responsibility of the Government of India, not of the State Government. The Defence Minister is sitting next to the Home Minister. He could have easily asked

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

him whether troops have been reduced or not reduced. Do we have to depend on the State Government of Jammu and Kashmir for this information that troops have been reduced or not reduced?

As I said, Sir, the second issue here is that let us not reduce cross border terrorism to mere figures, The figures of terrorists have gone up. The number of infiltrators has gone up by 300 per cent. The number of incidents has declined, which means that the terrorists who have come form acorss the Line of Control have come here for picnic. Is that what the hon. Home Minister is telling the House? Sir, my specific question is this. Mr. Janeshwar Mishra, the hon. Member has asked, "whether due to the lax policies of this Government.....,". And, they are saying, "pro-active tackling against terrorist within Jammu and Kashmir." This Government, Sir, in a joint statement with President Musharraf of Pakistan said that they will not allow terrorism to impede the peace process. This is a statement which has been repeated by this Government. And we pointed out even at that time that you are encouraging terrorism by making a statement of this kind. Add, this is exactly the point that Pakistan is making now that why have you called off the Foreign Secretary level talks because of Mumbai blasts. You should not have, because terrorism cannot be allowed to impede the peace process. My point is, it is a lax policy, it is a soft peddling with Pakistan which is indulging is cross border terrorism. And, if we do not take strong measures,if the barbed wire tencing is weakened somewhere, then it is up to the the hon. Defence Minister and his Ministry to strengthen it.

The second part of my question is this. He has said about Hurriyat. "that dialogue will go on with all those who abjure violence and other means." My specific question is: Has the Hurriyat abjured violence? Do you have a written commitment from them that they have abjured violence and that is why you are talking to them?

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: Sir, it is very good that we are discussing this issue in this House. It would have been proper if we had more time to discuss this issue in a greater detail so that all aspects relating to it could have been put before the House. Sir, one of the things which has to be borne in mind is that the barbed wire fencing has been repaired. But for some it could not be repaired because an earthquake had taken place and there was snow and all those things.

The second most important thing which has to be borne in mind is that the infiltrators are not coming from across the border only, they are going to the other contries and, then, migrating to India and to Jammu and Kashmir. Sometimes, they go to our neighbouring countries and from there they come. Now, the sea route is also open to them.

SHRI YASWANT SINHA: Sir, he must give us the figures because the statement here clearly states, "an estimated number of 299 terrorists infiltrated from across the border." Which border? If they have come from Bangladesh, give us the figures. Out of there 299, how many have come from Bangladesh, how many have come from Maldives, how many have come from Nepal, and how many have come from Bhutan?

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: I would be in a position to give replies to all these detailed questions if there is a detailed discussion. The question asked was whether infiltration has gone up or not. We are not saying that infiltration has not gone up. We are saying that the incidents have come down. Now, you please hear me first. Now, I am giving you the information that the infiltration is taking place across the border. Infiltration is taking place from the borders, which are not with only one country, but other countries also. Sometimes, the air route is also used. Now, these factors...(*Interruptions*)..

SHRI YASHWANT SINHA: But, Sir, this 299 is from Pakistan or....(*Interruptions*)..

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: This is little too much.

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI YASHWANT SINHA: No, I am confused, absolutely confused.

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: This is little too much....(*Interruptions*).. This is little too much. Not to be confused, you shall have to hear me first.

SHRI YASHWANT SINHA: No, that is your trademark. you always confuse.

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: But if you get up every now and then, you will get confused. Please hear me. You may not agree with me. Sir, we are not hiding anything from the House. It is not in the interest of the Government, or, the country. Whatever facts are there, I am putting before you. We have

said that infiltration has gone up. What we have said is the number of incidents has come down, the number of killings has come down, the number of casualties of the terrorists has gone up, the number of casualties of the security forces has come down. These figures too go to show this. Wherever we give the figures, you object to the figures and you ask us to depend on your own assessment which is tinged with politics. This cannot be done. So, to come to the correct conclusions, let us not discuss.....(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this is an unwarranted allegation that the Minister....(*Interruptions*).. Where is politics in this?...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Now, Sir, you shall have to help me...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this is an unwarranted allegation that the Minister...(*Interruptions*)... Where is politics in this?...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: This is really too much...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: Where is politics in this?

MR. CHAIRMAN: There is no allegation.

SHRI SHIVRAJ V.PATIL: Sir, if you want to give him a second chance, I have no objection. But every sentence...(*Interruptions*)...

MR.CHAIRMAN: Please come to the point.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Now, this is the position, Sir. Nobody is saying that situation in Jammu and Kashmir is totally under control, and no terrorist activity is taking place. The only point we are making is that in some respects it has gone up, in some respects it has come down. As far as the infiltration is concerned, it has gone up: as far as the incidents and killings are concerned, it has come down. There is nothing which is hidden from the Members of this house, or the country. Everything is plainly put on the Table for the Members to see. Now, you may suggest to us as to how and what can be done in order to improve upon the situation, we will accept it. But if your intention is to only find faulty with those who are sitting on the Ruling Benches, well, I can't help it.

MR.CHAIRMAN: Okay, Dr. Karan Singh.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, he did not answer the second part of the question, that is, Hurriyat. Where is Hurriyat?...(*Interruptions*)... Have they abjured violence?

MR. CHAIRMAN: You put another question.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I agree with the hon. Home Minister when he says that this whole matter needs a much deeper discussion than we can do in the course of a Question Hour. However, there is one very disturbing fact with which I am sure all of us are concerned and the Government of Jammu and Kashmir is very concerned, and that is the considerable increase in infiltration. The incidents may be less now, but, surely, the people who have infiltrated in large numbers are there in order to create incidents in the future. So, therefore, the fact that infiltration has considerably increased in the last few months is a matter of very grave concern. That is the first point, I think, you must be clear about. Whether the incidents so far are less than the last year is not really the point. We are still in July. There is still a lot of the year to go. This is number one. Number two, Sir, the fencing which has been put up by the Defence Ministry with great difficulty and great expenditure, the problem is that in winter it gets snowed under, and, therefore, it is easy to cross. It gets damaged. By the time snow melts and the army starts repairing the fence, the snow comes on again. And, there has been, as has been pointed out, and I think as the Home Minister himself has said, there have been breakdowns in the electrical supply for various reasons. Now, you don't have to have the whole fence breaking down. Even a break down in one sector is enough to allow a large number of people to come over. Therefore, I would say, (a) because of the increase in infiltrators, we have to be very careful, we must expect an exponential increase in incidents for the remainder of the year. I hope that does not happen. Number two, regarding the fence, I think, Sir, innovative and effective measures need to be taken to ensure that it is always electrified and in order. Thank you.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make.

We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary delegation from Belarus, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency, Mr. Gennady Vassilievich Novitsky, Chairman of the Republic of Belarus National Assembly Council of the Republic of the 3rd Convocation.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Belarus. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and friendly people of Belarus.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS — Contd.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, if you allow me, I will reply to a part of the question of the hon. Member. Now, one question which was put was, why it was necessary for the Home Ministry to get the information from the Government of Jammu and Kashmir with respect to the troops.

Sir, the question is that the security in Jammu and Kashmir is looked after on the Line of Control by Army, in other areas by paramilitary forces, and then there is the State Police. That is why to get the complete information, we were depending on the information coming from Jammu and Kashmir: and there is a system, there is a Unified Command in Jammu and Kashmir. It means, the Chief Minister sits there and the Army officers and the paramilitary officers and the State officers report to him, and if any action has to be taken, they decide in that committee meeting. So, at places, the Army is thinned out: at places, the paramilitary forces are inducted; at places, the State Police is inducted and the arrangement is done. That is why we were depending on that. Otherwise, we could have had the information from the Defence Ministry here, but that would have been limited to the Army only, and not to the other forces.

Now, as far as the other part of the question is concerned, that was a three--in-one question . And, the other part of the question, the last part, the third part of the question is this. Well, they give us the impression, the Hurriyat gives us the impression, that they would like to discuss this issue rather than to have a recourse to armed struggle or violence. And, we have decided to talk to those people who are willing to talk and willing to abjure violence. That is the point. Now, what they are actually doing and all those things, it is for the people to see.

As far as the question asked by the hon. Member here, Sir, he is very right that when the inflitration goes up, the chances of incidents also go up, and we shall have to be very careful. We will definitely bear this in mind to see that there are no more incidents and there is no increase in the incidents that would take place there.

As far as the fencing on the border is concerned, the Army is careful, the paramilitary forces are careful and the Government of Jammu and Kashmir and we are also careful. We will certainly look into it. But when in the border areas, which are at a distance from the places where the repairs can be done, if somewhere, some mistake happens, we would look into it as to how to overcome and repair and correct that mistake in the machine in time. We would also look into it. We will definitely bear in mind the concern expressed by the hon. Member here that the number of incidents and the killings should also go down.

MR. CHAIRMAN: That is enough. Mr. Ramachandraiah.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Mr. Chairman, Sir, part of the question which I intend to ask has been answered, but I want to ask the Minister one thing. Sir, I should congratulate him when he says that infilitration has gone up but the number of incidents has come down. But as the other hon. Member said, we have allowed the robbers to enter our house but not to rob our house . One day or the other, they are going to rob us. And, that is what is happening in the country. I do not know to what extent you are successful in arresting the imfitlration on the Northern front. But, as far as the North-Eastern front is concerned, is it not true that the political dispensations in those States are rather complacent in preventing the migration from across the border? So, ultimately, now it has led to the infiltration of terrorists from these softer points, from porous points. What exactly is the Government contemplating to arrest the infiltration on the North-Eastern front?

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Shourie.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, is it irrelevant?

MR. CHAIRMAN: No, but you have gone to the North-East!

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: It needs to be admitted first.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: But ultimately, it is related to infilitration, the infiltration of terrorists into the country.

MR. CHAIRMAN: Please, put a separate question.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I do not understand why it has been rejected.

MR. CHAIRMAN: It has not been rejected.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, is it not related to terrorism and infiltration in this country?

MR. CHAIRMAN: Let him speak. This question has already taken too much of the time.

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, from what the Home Minister just said, there is infiltration not only from across the J&K border, but from all sides. Checking that is also somebody's responsibility. So, the question really cannot just be dismissed by saying, 'no people are coming from other sides'.

Sir, I would particularly request the hon. Home Minister to recall his own statement in this very House that 100 per cent of the recommendations of task forces set up after Kargil, including the Task Force on Border Management, have been implemented or are in the process of being implemented. Those recommendations dealt precisely with how to check infiltration and what to do about it. He is now saying what are the suggestions that this side has to offer. Those suggestions have been listed, *ad infinitum*, including by those task forces, which he said have been implemented. So, if this is the result after that, then we really do require, what Dr. Karan Singh has said just now and what the Home Minister himself was saying , a very detailed discussion on the subject. And my question is whether you and the Home Minister would agree to that.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it goes without saying that when Mr. Arun Shourie gets up and puts a question, I say 'Yes' to it! When he says that the number of the districts affected by naxalites has gone up, I had corrected it many times and yet, because Mr. Shourie says it, people accept it. I shall have to explain it again and here also...(*Interruption*)...

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI ARUN SHOURIE: Actually, Sir, they have done a very interesting thing under the Ministry. They have changed the definition of what is 'affected'. You will come to that in the afternoon.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the simple and direct reply is, 'yes, I am ready'!

SHRI ARUN SHOURIE: That is wonderful!

श्री सभापति: श्री सी॰ राम चन्द्रैय्या जी के प्रश्न का भी आप उत्तर दे दीजिए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am sorry that I do not have the requisite information available with me about infiltration in other States. But there also, the position has improved and there, there is not so much a question of infiltration as the terrorists modules are working over there and creating problems. But if this question were to be separately asked, I would definitely try to reply to it in a littel more detail. The situation in the North-East has also improved. There is no question of increase in infiltration as such in the North-Eastern States. Some infiltration is there, but, in my opinion and as per the information available with me at present, there has been no increase in the infiltration.

*43. [The questioner SHRIMATI S.G. Indira was absent. For answer *vide* page 30.]

Special Economic Zones

44. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many SEZs are at present operational in the country, State-wise;